MR. CHAIRMAN: Dr. Farooq Abdullah.

DR. FAROOQ ABDULLAH:Sir, my question has been answered.

श्री बनवारी लाल कंछल: सर, जब हमारे देश में खाद की कमी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो साग-सब्जी बेचने के लिए कॉर्पोरेट घरानों को आप लगा रहे हैं, क्या उनके द्वारा आप खाद के कारखानों को लगाने के लिए भी कोई योजना बनाएंगे? जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियों में होता है कि यह माल लोगे तो इसके साथ यह भी लेना पड़ेगा, उसी तरह क्या इन कॉर्पोरेट घरानों को भी आप कहेंगे कि अगर आप शॉपिंग मॉल खोलेंगे तो आपको खाद की फैक्ट्री भी खोलनी होगी? क्या आप कोई ऐसी योजना बनाएंगे?

श्री राम विलास पासवान: इन्होंने एक नया सुझाव रखा है, उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं।

कृषि के बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच तालमेल

*222. **श्री रूद्रनारायण पाणि:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनका मंत्रालय राज्यों के कृषि विभागों के साथ किस प्रकार तालमेल रखता है;

(ख) क्या हाल ही में दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों का कोई सम्मेलन बुलाया गया था;

(ग) देश में किसानों के वास्तविक कल्याण के लिए अब तक कितनी धन-राशि व्यय की गई होगी;

(घ) क्या कृषि बजट को लेकर राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच अब तक कभी कोई टकराव की स्थिति पैदा हुई है; और

(ङ) क्या सरकार 'कृषि बजट' को 'रेल बजट' की तरह तैयार किए जाने पर विचार कर रही है?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) चूंकि कृषि राज्य का विषय है इसलिए कृषि के विकास हेतु नीति और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की होती है और भारत सरकार उचित वित्तीय एवं नीतिगत समर्थन के जरिए राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण करती है। कृषि मंत्रालय विशेषकर राज्यों की बैठकों और सम्मेलनों यथा-खरीफ/रबी सम्मेलन के जरिए राज्यों के कृषि विभागों के साथ समन्वय करता है ताकि कृषि के विकास, अपेक्षित परामर्श के बाद राज्यों की वार्षिक कार्ययोजनाओं के अनुमोदन और मानेटरिंग की प्रक्रिया के जरिए मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों पर उनकी राय, सुझाव और फीड बैक प्राप्त किए जा सकें। राज्य सरकारों से भी महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों पर परामर्श लिया जाता है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय दिनांक 23.12.2006 को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के राज्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में राज्यों से परामर्श लिया गया।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि मंत्रालय के तहत तीन विभागों का योजना परिव्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	विभाग	2005-06	2006-07	2007-08
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	4179	4800	5520
2.	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	669	777	910
3.	कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	1150	1350	1620

मंत्रालय की सभी योजना स्कीमें किसानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ एवं कल्याण के लिए हैं। किसानों के लाभ के लिए कुछ कल्याण उपायों में शामिल है - राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम, किसानों तक ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए व्यापक ऋण पैकेज, किसानों को 3 लाख रुपये तक के फसल ऋणों पर 7 प्रतिशत वार्षिक तक के ब्याज दर में कमी तथा कुछ पहलें जिनमें बजट 2008-09 में घोषित किसानों की ऋण माफी शामिल है।

(घ) तथा (ङ) जी, नहीं।

Coordination between States and Central Government on Agriculture

†*222. SHRI RUDRA NARAYAN PANY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) how his Ministry co-ordinates with the Departments of Agriculture of the States;

(b) whether recently any conference of the Ministers of Agriculture of the States was convened in Delhi;

(c) the amount that would have been incurred on the genuine welfare of farmers in the country; so far;

(d) whether any conflict has arisen between the Central Government and the State Governments on the agriculture budget so far; and

(e) whether Government is contemplating to prepare 'Agriculture Budget' on the lines of 'Railway Budget'?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As Agriculture is a State subject, the States are responsible for implementation of policy and programmes for development of agriculture, and the Government of India supplements the efforts of the States through appropriate financial and policy support. The Ministry of Agriculture coordinates with the Departments of Agriculture of the States mainly through meetings and conferences of States, such as Kharif/Rabi Conference to obtain their views, suggestions and feedback on different programmes and policies of the Government for development of Agriculture; approval of Annual Work Plans of States after due consultation, and through the process of monitoring the implementation of different schemes sponsored by the Ministry. State Governments are also consulted on important policy measures. For example, while considering the recommendations of National Commission on Farmers, States were consulted in a Conference of State Ministers of Agriculture and Allied Sectors on 23.12.2006.

(c) The Plan Outlay of the three Departments under the Ministry of Agriculture during the last three years is as under:

(Rs. in crores)

Sl.No.	Department	2005-06	2006-07	2007-08
1.	Department of Agriculture & Cooperation	4179	4800	5520
2.	Deptt. of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	669	777	910
3.	Deptt. of Agricultural Research & Education	1150	1350	1620

† Original notice of the question was received in Hindi.

All the Plan Schemes of the Ministry are for the direct or indirect benefit and welfare of farmers. Some of the welfare measures for benefit of farmers include National Agricultural Insurance Scheme, Comprehensive Credit Package to increase flow of credit to farmers, reduction of rate of interest on crop loans to farmers upto Rs. 3 lakh to 7% per annum and some of the initiatives, including waiver of debt of farmers announced in the Budget 2008-09.

(d) and (e) No, Sir.

श्री रूद्रनारायण पाणि: सभापति महोदय, धन्यवाद। विपक्ष क्रमांक-'1' यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्ष क्रमांक-'2' यानी UNPA और हमारे वामपंथी मित्र, जो कि सरकार को बाहर से समर्थन तो देते हैं, लेकिन अंदर कटु से कटु भाषा में आलोचना करते हैं ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री रूद्रनारायण पाणि: इनके कारण कम से कम आखिर में देश के गरीब किसानों को कुछ मुआवज़ा मिला है। किसानों का कर्जा माफ करने की सरकार ने यह जो नीति अपनाई है, यह हमारे विपक्ष की मांग के कारण ही किया गया है ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री रूद्रनारायण पाणि: हमारे माननीय कृषि मंत्री, श्री शरद पवार जी बहुत पावरफुल मंत्री हैं और पुराने लगभग छत्तीस साल से पावर में हैं ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: देखिए इस वक्त आप केवल सवाल पूछिए।

श्री रूद्रनारायण पाणि: सर, मेरे प्रश्न के भाग 'ग' में यह पूछा गया था कि गत सालों में किसानों के हितार्थ कितना व्यय किया गया है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने केवल तीन साल का ब्यौरा दिया है। मैं आशा कर रहा था, चाहे आप 36 साल से कहिए या देश के आजादी के बाद से कहिए, लेकिन किसानों के हित में केवल तीन साल का विवरण दिया गया है कि उन पर इतना व्यय किया गया। अगर देश की आजादी के बाद भिन्न-भिन्न सरकारें ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Please put the question. ...*(Interruptions)*...

श्री रूद्रनारायण पाणि: किसानों के हित में लाखों-करोड़ों के व्यय कर रहे हैं, तो मेरा यह कहना है ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Mr. Pany, you will be disallowed to put your supplementary, if you do not put the question. ...*(Interruptions)*... Please resume your seat.

सुश्री मैबल रिबैलो: सर, इतना लम्बा क्वेश्चन ..(**व्यवधान**)

श्री रूद्रनारायण पाणि: सर, आप इनको बैठाइए ना, यह क्या कर रही हैं ...(**व्यवधान**) सर, इनका सब्जैक्ट मैटर क्या है? ...(**व्यवधान**)

सुश्री मैबल रिबैलो: सर, यह जो बोल रहे हैं ...(**व्यवधान**)

श्री रूद्रनारायण पाणि: सर, इनका सब्जैक्ट मैटर क्या है? ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat. ...*(Interruptions)*... Please do not interrupt. ...*(Interruptions)*... Please do not interrupt. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please ask the question. *(Interruptions)* Mr. Pany, you will be disallowed of your supplementary if you do not ask the question. *(Interruptions)*. Please do not interrupt.

श्री रूद्रनारायण पाणि: इनका इंटेंशन क्या है, सर? ...(व्यवधान) इनका सब्जैक्ट मैटर क्या है ...(व्यवधान)... इनका सब्जैक्ट मैटर क्या है, सर ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt. *(Interruptions)*

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: What is their subject-matter? *(Interruptions)* इनका सब्जैक्ट मैटर क्या है? ...(व्यवधान)... What is her subject matter, Sir?

MR. CHAIRMAN: Ask the question, or forego your chance. *(Interruptions)*

श्री रूद्रनारायण पाणि: सर, इस unnecessary disturbance के बावजूद मैं आपके माध्यम से इनसे यह प्रश्न करता हूं कि अगर कई सरकारें देश के किसानों के लिए लाखों-करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, तो क्या केन्द्र की सरकार वर्तमान कृषि को समवर्ती सूची में लाने के लिए सोच रही है? दूसरा यह है सर कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सिर्फ एक सवाल ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: सर, यह इसका पार्ट बी है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप पहली सप्लिमेंटरी पूछ रहे हैं या दूसरी?

श्री रूद्रनारायण पाणि: सर, यह इसका पार्ट बी है ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: There is no part (b). Only part one.

श्री रूद्रनारायण पाणि: सर, जब हम भाषण करते हैं, तो कहते हैं कि इतने-इतने किसानों ने आत्महत्या की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सीधा प्रश्न करता हूं कि अब तक कितने किसानों ने, गरीब भाइयों ने आत्महत्या की है? क्या इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट इनके पास है?

MR. CHAIRMAN: Question please. Only question, please. Let me make one thing clear. The hon. Member has made statement instead of asking supplementary. The Chair rules that his second supplementary will not be allowed. Mr. Minister, please answer the question.

SHRI SHARAD PAWAR: To the first question which the hon. Member has asked, my reply is 'no'.

SHRI MANOHAR JOSHI: Mr. Chairman, thank you very much. I would like to know from the hon. Minister in connection with answers to question parts (b) & (e), where the reply is 'no'. My specific question is on the same issue. The hon. Minister, when he was in Maharashtra, made an announcement that the Government will consider increasing the limit of two hectares for waiver of debt. Therefore, I would like to know whether this was brought to the notice of the Agriculture Minister before the Budget was prepared, because the Minister is aware that, always, when the Finance Minister makes a statement here, he consults the Ministers in advance. I would like to know whether in this particular case, it was done or not; because, after the Budget, in Vidarbha region in Maharashtra, 34 farmers have committed suicide. I would like to know whether the Minister was aware that such things might happen and whether this proves that there is a difference of opinion between the hon. Prime Minister and the Finance Minister and also between the Finance Minister and the Agriculture Minister.

On the same question, lastly, a number of times we have made a demand in the House that the Budget for farmers in the country should be an independent separate Budget as there is the Railway Budget. I would like to know whether the Minister agrees with this. Looking to his experience, I would like to know whether he would like to take steps in this regard.

SHRI SHARAD PAWAR: The hon. former Speaker has put two questions. The first question is about differences among the hon. Prime Minister the Finance Minister and the Agriculture Minister. My reply is, there is no difference. Whatever is the decision, it has been taken collectively.

Regarding a separate Budget for agriculture, yes, this particular demand has been made on many occasions by many hon. Members; also, there are write-ups in some of the newspapers. We have to keep in mind that the agricultural sector has inter-sector linkages to water resources, irrigation, fertilizer, rural development, finance, cooperation, power, etc. There are separate Ministries for these issues. Hence, it is not possible to bring all these under one umbrella and one Ministry. That is why meeting the demand for a separate Budget for agriculture is not possible.

DR. K. MALAISAMY: Sir, I would be brief as Mr. Chairman has directed. Sir, the role of Centre, as seen from the Minister's reply is to give financial and policy support to the States and it is okay. I am interested to know whether the total number of people who are involved in the agricultural operation in the country and the allocations given by the Centre are in proportion to each other? In other words, supposing 70 per cent are involved in agriculture, what is the total allocation they get out of the total Budget?

SHRI SHARAD PAWAR: In fact, one has to study the Budget but I have to just explain one thing that the total number of farmers in this country are somewhere near 12 crores. These are called in Hindi, *Khatedars,* i.e. who own the actual land. They are about 12 crores and if you see in the last two to three years, there is a consistent rise in Budgetary provision for agriculture from this Government.

DR. K. MALAISAMY: My question is whether it is in proportion to the total agriculture.

श्रीमती वृंदा कारत: सर, मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि कई प्रदेश सरकारों की तरफ से धान की एम॰एस॰पी॰ बढ़ाने के बारे में आपके पास request आई है, क्या आपने इस बारे में कोई विचार किया है और क्या आप इस संबंध में इस सदन में कोई आश्वासन दे सकते हैं?

SHRI SHARAD PAWAR: In fact, recently we have received the report of the CACP. As per our normal practice, whenever we get this type of report or recommendation from CACP we have to consult all the State Governments. We have written to all the State Governments and sent the synopsis of the CACP to all the paddy growing States. We are expecting their comments and then a final view will be taken.

MR. CHAIRMAN: Question No. 223.

श्री संजय राउत: सर, बाकी लोग भी बैठे हैं, हम को भी मौका दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री के॰बी॰ शणप्पा: सर हम को भी मौका दिया जाए। ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपको मौका मिलेगा। ...(व्यवधान)...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: सर ...(व्यवधान)... मौका दीजिए।

श्री सभापति: Please, please allow the Question Hour to proceed. *(Interruptions)*

श्री रूद्रनारायण पाणि: सर, यह अन्याय है ...(व्यवधान)...

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: सर, अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं। जब से सदन शुरू हुआ है, मैं हाथ उठाता हूं और आप कभी मौका नहीं देते। यह मुझे बहुत अदब के साथ ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज ...(व्यवधान)... प्लीज ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: सर, सब लोग स्टेटमेंट करते हैं ...(व्यवधान)... मेरे साथ अन्याय हुआ है। ..

श्री के॰बी॰ शणप्पा: सर, आप हमारे custodian हैं ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please resume your seats.

Review of policy of permitting big retail corporates

*223. SHRI SANTOSH BAGRODIA:††
SHRI KALRAJ MISHRA:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government has lately reviewed its policy on permitting big retail corporates to expand their footprints in retail markets, so as not to hurt local groceries, including vendors of vegetables and fruits;

(b) if so, the decisions taken in the matter to protect the interests of small retailers and consumers; and

(c) the steps taken and the directions issued by Government in this regard?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The retailers/traders register their shops with concerned authorities in various States. Presently, there is no restriction on the entry of any domestic investor into retail sector. So far as Foreign Direct Investment is concerned, as per extant policy, the Government allows 100 per cent foreign direct investment (FDI) in cash and carry through the automatic routs and 51 per cent in single brand.

. (b) and (c) Department of Industrial Policy and Promotion have on 20-3-2007 sanctioned a Study on "The Impact of organized Retailing on the Unorganized Retail Sector" to be carried out by International Council for Research on International Economic Relations (ICRIER). The Study will, *inter alia*, cover effect on organized retailing on small retailers and vendors in the unorganized sector keeping in mind the likely growth in the overall market and effect on employment. The recommendations and findings of this study will enable the Government to take a view on the need to have a policy on organized with regard to its overall impact. ICRIER was to submit the final Report in July, 2007 but has sought change in time schedule to enable additional survey for the study. The Final report by NCAER is scheduled to be submitted by May, 2008.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Chairman, Sir, I refer to the reply, to what the hon. Minister has given. I will just quote the operative part of it. It says. "...the Government allows 100 per cent FDI in cash and carry through the automatic route and 51 per cent in single brand." Then, in the second part he says, "The final Report by NCAER is scheduled to be submitted by May 2008." Does it mean to say that the Government has taken all these decisions about FDI, automatic route and in single brand even before getting the report? If it has already taken and the report says that the decision taken is not right, is it possible that the Government will be able to change it because those investments have already come to India? What is the importance of this kind of report being made now? That is one thing, Sir. In the

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Santosh Bagrodia.